तय समय में आसानी से औद्योगिक मंजूरी की जरूरत

- उद्योग समागम बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जताई आवश्यकता
- बोले-ऐसी प्रणाली बना रहे हैं, जिससे उद्यमियों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी

नई दिल्ली में गुरुवार को उद्योग समागम में बोलते केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ● एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में कारोबारी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वास्तविक रूप में एक सिंगल विंडो की जरूरत है। उनका कहने का अभिप्राय यह था कि कहने के लिए तो सभी जगह सिंगल विंडो होते हैं, लेकिन उद्यमियों को उस सिंगल विंडो पर तमाम जरूरी मंजूरी नहीं मिल पाती हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के साथ उद्योग समागम नामक बैठक के संबोधन में गोयल ने कहा कि अगर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश औद्योगिक मंजूरी के लिए एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं तो सभी राज्यों में वैश्विक निवेश होगा। समागम में 16 राज्यों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की।

गोयल ने कहा कि राज्यों में औद्योगिक मंजूरी निर्धारित समय में आसानी से देने की जरूरत है। हमलोग ऐसी प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिसके तहत औद्योगिक या कारोबारी मंजूरी के लिए उद्यमियों को सरकारी कार्यालय या सरकारी कर्मचारियों के पास आने की जरूरत नहीं हो। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सभी सेक्टर में मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे रोजगार के अधिक अवसर निकलेंगे। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सभी राज्यों में एक समान अवसर का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस प्रयास से हो रहे विदेशी निवेश से सभी राज्यों को लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार बहुत ही गंभीरता से भारत को विदेशी निवेश का बड़ा केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत है। गोयल ने कहा कि औद्योगिक विकास को लेकर जिन राज्यों ने अच्छी पहल की है, उससे अन्य राज्यों को सीखने और उसे अपनाने की जरूरत है। जैसे राजस्थान की पर्यटन तो सिक्किम की आर्गेनिक फार्मिंग नीति से अन्य राज्य सीख सकते हैं। गोयल ने राज्यों से कहा कि निर्यात प्रोत्साहन सिर्फ केंद्र का काम नहीं है। राज्य व केंद्र को मिलकर इसे बढ़ाना होगा। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। 13 को मुंबई में बोर्ड आफ ट्रेड की बैठक में निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष चर्चा की जाएगी।

गुणवत्ता वाले इस्पात को बढ़ावा देने के लिए उपाय खोजे उद्योग

पीयूष गोयल ने इस्पात क्षेत्र में सतत मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात उद्योग की शीर्ष हस्तियों के साथ कार्बन सीमा समायोजन कर पर चर्चा करने का गुरुवार को सुझाव दिया। उन्होंने उद्योग से 2047 तक 50 करोड़ टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखने को भी कहा। अभी उद्योग की नजर 2030 तक 30 करोड़ टन उत्पादन करने पर है। एक आनलाइन सम्मेलन में गोयल ने उद्योग को कार्बन उत्सर्जन कम करने और उच्च उत्पादकता तथा गुणवत्ता वाले इस्पात को बढ़ावा देने के लिए नए और बेहतर तरीके खोजने का भी सुझाव दिया।